

महाकाल सवारी मार्ग पर एक और नवाचार, मकान दुकान पर एक जैसे रंगों की बहार

- ▶ महाकाल सवारी मार्ग का विस्तृत बनाया जा रहा मास्टर प्लान
- ▶ साइड बोर्ड से लेकर घरों तक का कलर एक जैसा रखने की योजना
- ▶ 83.78 करोड़ों की लागत से विस्तृत मास्टर प्लान हो रहा तैयार

सवारी में नए-नए प्रकल्पों की शुरुआत की जा रही है, इस बार सवारी में जिस प्रकार से सेना का बंड आया, ऐसे में यह भी योजना तैयार की जा रही है की सवारी मार्ग में आने वाले सारे मकान एकरंग में रंगे में होवें दुकानों के बाहर लगे बोर्ड भी एकरूपता में हों।



स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा एक प्रेजेंटेशन देखा गया है, जिसमें पूरी योजना विस्तृत तौर पर बनाई जा रही है, सब कुछ ठीक रहा तो महाकाल सवारी मार्ग का विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं और शहरवासियों को लुभायेगा, इसके लिए मंगलवार को एक अहम बैठक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई। उज्जैन में महाकाल सवारी मार्ग पर हेरिटेज

मास्टर प्लान 2035 पर मंथन महाकाल की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, उसके अनुसार योजना की अनुमानित लागत 83.78 करोड़ से सड़कों का चौड़ीकरण, भूमिगत सर्विस (पानी, सिविल, नाली, बिजली सहित) पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल सड़क, पैदल मार्गों का पूर्ण निर्माण, रामघाट तथा महाकाल चौराहे पर सवारी द्वार एवं रामघाट पर पूजा स्थल का निर्माण, मार्ग में ऐतिहासिक धार्मिक स्मारकों संरचनाओं में

सवारी मार्ग पर यह सुविधा रहे

महापौर मुकेश टटवाल द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महाकाल सवारी मार्ग विकास योजना के अंतर्गत जो कार्य योजना बनाई गई उसपर शीघ्र ही शासन से स्वीकृति प्राप्त की जाए, योजना में सवारी मार्ग के भवनों के एक रंग में होने, दुकानों के बोर्ड एक समान हो, मार्ग पर वृद्ध एवं दिव्यांगजन हेतु स्थान का निर्धारण सहित अन्य आवश्यक बातों को सम्मिलित करने हेतु कहा गया।

सुधार, सड़क किनारे दुकानों और संपत्तियों का समरूप, महाकाल सवारी की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली

मूर्तियां, स्मार्ट एलडि लाइट के साथ हेरिटेज स्टाल में बैठने की व्यवस्था के साथ सड़कों का निर्माण, रेलिंग एवं पार्किंग

व्यवस्था, फ्रेश रूम, सूचना बोर्ड, मार्ग संकेतक, पीए सिस्टम एवं निगरानी प्रणाली के साथ ही परियोजना क्षेत्र में अन्य निर्माण के लिए विनियामक दिशा निर्देश की सुविधा महाकाल सवारी मार्ग में होगी।

ये रहे मौजूद

बैठक में एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी, सत्यनारायण वेदान, कैलाश प्रजापत, प्रकाश शर्मा, राजत मेहता, अपर आयुक्त स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवदा, संजय शावक, कार्यपालन यंत्री साहित मैदवाला एवं पलाश शर्मा आदि मौजूद रहे।

उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी

पटवारी ने सिंधिया, सरकार और मंत्रियों पर साधा निशाना, गिरफ्तारी देने अशोकनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष

अशोकनगर, 8 जून. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को अशोक नगर एक एफआईआर मामले में अपनी गिरफ्तारी करने पहुंचे। गिरफ्तारी से पहले पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए एक शेर पढ़ा और वाहवाही लुटो। यह शेर उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए पढ़ा। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने यह शायरी घमंड से की थी। पटवारी ने कहा, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हैं तो जिंदा रहना



जरूरी है, जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने विघटन पैदा करने का काम किया। जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि आप यहां से सांस दें।

पूछकर उसका वीडियो वायरल किया। मैंने बालिग बच्चे से पूछकर वीडियो डाला था। इस दौरान उन्होंने उमाभारती और प्रह्लाद पटेल को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि एक व्यक्ति जिसे मानव मल खिलाना गया था, उसने कई जगह शिकायत की मगर प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन वह व्यक्ति मुलाकात करने अशोकनगर से ओरछा पहुंचा और उसने हकीकत बयान की। पटवारी ने कहा कि राजनीतिक

पुलिस ने तुरंत रिहा भी कर दिया

प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह किया। प्रदेशभर से नेता और कार्यकर्ता यहां पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी देने पहुंचे। विधायकों और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के काफिले को पुलिस ने जगह-जगह चौकियों के लिए रोका। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें रोकने के लिए 8 जिलों की पुलिस बुलाई गई। पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ता का जहां पसीना गिरेगा, वहां मेरा, कांग्रेस के नेताओं के खून की अंतिम बूंद भरी गिरेगी। कार्यक्रम के अंत में एसडीओपी विवेक शर्मा ने अशोक नगर में मंच से जीतू पटवारी सहित न्याय सत्याग्रह में उपस्थित सभी लोगों को गिरफ्तार किया और तत्काल रिहा भी कर दिया गया।

जरूरत के लिए समाज की सियासत करना उमा भारती, प्रहलाद पटेल की पहचान है।

लेकिन, ये तब चुप क्यों रहते हैं, जब इनके समाज बंधु संकट में रहते हैं।

सड़क किनारे मिला विधायक प्रतिनिधि धाकड़ का शव

हत्या की आशंका

नवभारत न्यूज रतलाम/ आलोट. आलोट विधायक के प्रतिनिधि का सड़क किनारे रात को शव मिला। सूचना पर मंगलवार सुबह घटनास्थल पर डॉंग स्कॉयड की टीम भी पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। जहां पर कन्हैयालाल धाकड़ की मोटरसाइकिल चप्पल पड़ी हुई थी। एस्पपी ने एसआईटी का गठन किया है।



मालवीय के विधायक प्रतिनिधि हैं, सोमवार की रात को सरसी और केरवासा के बीच सड़क पर मोटरसाइकिल गिरी हुई तथा उनका शव मिला। बेटे अजय धाकड़ ने हत्या की आशंका जताई है। अजय ने बताया कि करीब 8-10 दिन पूर्व सरकारी जमीन को लेकर विनोद खारोले और शहाजाद से विवाद हुआ था। बीती शाम पापा किसी मित्र के जन्मदिन के आयोजन में शामिल होने के लिए उपलब्ध गांव गए थे। रात को गेहूं की ट्राली भरकर रखना। सुबह रतलाम मंडी जाना है। इसके तकरबन आधे घंटे बाद ही दुर्घटना की सूचना मिली।

एक नजर में

रियल एस्टेट दिग्गज बनाएं शहरी विकास का ब्लूप्रिंट
भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मध्यप्रदेश के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। इससे बढ़ती नगरीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसे साकार करने के लिए मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्वलेव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट होराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टूमॉरो थीम पर केन्द्रित कॉन्वलेव में मध्यप्रदेश के शहरी विकास और निवेश पर देश की रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गज विकसित मध्यप्रदेश 2047 के लिए शहरी विकास के ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे।

रेल मंत्री वैष्णव के पिता के निधन पर शोक जताया

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊ लाल वैष्णव के निधन पर गहन दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वैष्णव परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रौचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजन को सह दुःख सहन करने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि स्व. वैष्णव बीते कुछ दिनों से गंभीर रूप से अस्वस्थ थे।

गर्भवती को कंधे पर लाद कर पहुंचे अस्पताल

घटना ने खोल दी सरकारी दावों की पोल

जबलपुर, 8 जुलाई. जबलपुर में बारिश इन दिनों लोगों पर खूब सितम ढा रही है, लेकिन मानसून की ये बरसात सरकारी बड़ईतजामों की पोल भी खोल रही है। ताजा मामला जबलपुर के नजदीक दिव्यासा गांव का है, जहां खस्ताहाल सड़कों के कारण गांव की गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।



अभी महज कुछ ही दिनों की बारिश से शहर को जोड़ने वाली इस रोड के परखच्चे उड़ गए। रोड पूरी तरह बंदहाल हो गई। हालात ये हैं कि अब रोड की जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। सरकारी दावों की पोल उस समय खुल गई जब एक गर्भवती महिला को जननी एक्सप्रेस से शहर ले जाने के लिए

महिला को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा

लिहाजा जननी एक्सप्रेस मुख्य मार्ग पर जाकर ही रुक गई। जिसके बाद विव्यासा गांव के वाशिदे कुछ दूर तक शिखा चढ़ार को पैदल और उसके बाद स्ट्रेचर पर रखकर जननी एक्सप्रेस तक लेकर आए। इस दौरान महिला को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कड़ी मेहनत के बाद जननी एक्सप्रेस से महिला को अस्पताल भेजा जा सका। गांव के लोगों का कहना है की तहसील मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंचे मार्ग नहीं है और बारिश में हाल भी बुरे हो जाते हैं। वहीं जननी एक्सप्रेस में आए डॉक्टर का भी कहना है कि उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

90 करोड़ से चौड़ा होगा बीआरटीएस कॉरिडोर

प्राथमिक रिपोर्ट तैयार, स्मार्ट सिटी फंड से होगा काम

नवभारत न्यूज इंदौर. शहर की बीआरटीएस सड़क को तोड़कर चौड़ी करने की प्राथमिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। सड़क चौड़ीकरण पर 90 करोड़ लागत आएगी। इसके तहत नगर निगम स्ट्रॉट वॉटर लाइन, साइकिल ट्रैक और बिजली खंबे और हाइड्रेशन लाइन शिफ्टिंग का काम भी किया जाएगा। उक्त कार्य स्मार्ट सिटी फंड से किया जाएगा, इसकी स्मार्ट सिटी अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। नगर निगम बीआरटीएस एबी

डिटेल् प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि प्राथमिक रिपोर्ट मिल गई है और उसमें 90 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। सड़क चौड़ीकरण की डिटेल् प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कारवाय होगी।



चौड़ीकरण कार्य पर नगर निगम को 1090 करोड़ रूपए की लागत आएगी। यह पैसा स्मार्ट सिटी फंड से लिया जाएगा। उक्त खर्च की स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह की मंजूरी दे दी है।

मछुआरों के लिए बनेगा कमांड कंट्रोल रूम

आपात स्थिति में मछुआरों को मिलेगी शीघ्र सहायता

भोपाल में बनेगा केवट प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में मॉडर्न एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अहम पहल की जा रही है। केन्द्र सरकार की फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड योजना के तहत भोपाल में 5 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान में केज कल्चर, बायोफ्लोक, रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, मछलियों की हाइजेनिक हैंडलिंग, फिश प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यूएडिशन जैसे विषयों पर मछुआ समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मछुआओं को इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मछली पालन तकनीक की जानकारी और व्यावसायिक दक्षता प्राप्त होगी।

पहुंचाई जा सकेगी। ये पहल ब्रीडिंग ग्राउंड के चिन्हांकन के साथ मत्स्य आवेष्ट पर निगरानी को और ज्यादा आसान, सुलभ और प्रभावशाली बनाएगी। कमांड कंट्रोल रूम की मदद से मुख्यालय स्तर से ही 24गुणा 7 निगरानी संभव हो सकेगी। ड्रोन के माध्यम से जल क्षेत्र की लाइव मॉनिटरिंग और जीपीएस सिस्टम से नावों की ट्रैकिंग की जा सकेगी और आपात स्थिति में मछुआओं को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

विदिशा सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जारी रहेगा बारिश का दौर

नवभारत रिपोर्ट

भोपाल, 8 जुलाई. मप्र के रायसेन, विदिशा, रीवा, सतना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर जिलों में बुधवार को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को लेकर पूर्वानुमान लगाया है। इन जिलों में विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके साथ ही नर्मदापुरम, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योर पुरकला, दतिया, कटनी, राजगढ़, टीकमगढ़, शाजापुर और

छतरपुर सहित जिलों में भी

भारत की चुप्पी और किसानों की अनदेखी यह और भी चिंताजनक है कि भारत, जो इस कार्यकारी समूह का सह-अध्यक्ष है, ने अभी तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के किसानों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैसे संबंधित विभागों के साथ कोई राष्ट्रव्यापी परामर्श नहीं किया है। भारत के डॉ. सुनील अर्चक की सह-अध्यक्षता ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ा रही है, जिन पर देश के अंदर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है। भारत को अपनी समृद्ध जैव विविधता और अपने किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी। पूरी दुनिया के बीज क्षेत्र का केवल 1% एफएओ के लाभ-साझाकरण कोष में दान करने के बदले में हमारी पूरी आनुवंशिक संपदा को एमएलएस के लिए खोल देना भारत और वैश्विक दक्षिण की खाद्य संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है।

अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ

माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है, उत्तर-पूर्व अरब सागर से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्र तक तथा दक्षिणी गुजरात क्षेत्र, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिणी लखीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा से होकर माध्य समुद्र तल से 4.5 किमी से 7.6 किमी की ऊंचाई के मध्य निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंरचना तक विस्तृत है। दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है एवं माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई तक फैली हुई है।

एक नजर में

जैव विविधता बनाम कॉर्पोरेट लाभ

प्लांट ट्रीटी की बैठक में भारत के बीजों पर मंडराता खतरा

पेरू में पौधा आनुवंशिक संसाधन खाद्य और कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत बहुपक्षीय प्रणाली को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में सह-अध्यक्षों के प्रस्ताव नामक एक नया पैकेज ऑफ मेजर्स अंतिम रूप लेने वाला है, और चिंता की बात यह है कि इन सह-अध्यक्षों में भारत के डॉ. सुनील अर्चक भी शामिल हैं। यह स्थिति भारत की जैव विविधता और किसानों के अधिकारों के लिए एक गंभीर मोड़ है, जहाँ कॉर्पोरेट हितों का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। बीजों पर कंपनियों का बढ़ता नियंत्रण यह प्रस्तावित पैकेज ऑफ मेजर्स केवल वैश्विक बीज

साझाकरण का मसौदा नहीं, बल्कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे पौधों के आनुवंशिक संसाधनों (यानी, बीज) और उनसे जुड़ी डिजिटल जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है। किसानों के हक पर हमला और पेटेंट का खतरा: प्रस्तावित बदलावों से सभी पौधों के आनुवंशिक संसाधन एमएलएस के दायरे में आ जाएंगे, जिसका अर्थ है कि भारत को अपनी अनमोल जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा करना होगा, अपनी शर्तों पर नहीं। बड़ी कंपनियाँ इन देसी बीजों और आनुवंशिक सामग्रियों को आसानी से ले सकेंगी, उन पर पेटेंट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल कर सकेंगी। इसका सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा, जिन्हें भविष्य में अपने ही पारंपरिक

किसानों और जैव विविधता प्रेमियों की पुकार यह हमारे किसानों के पारंपरिक ज्ञान, उनकी मेहनत और उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। हमें भारत सरकार से अपील करनी होगी कि वह इस प्रस्तावित पैकेज ऑफ मेजर्स को तुरंत अस्वीकार करे, खासकर अनुबंध 1 के विस्तार के प्रस्ताव को। बीजों की चोरी और कॉर्पोरेट पेटेंट से सुरक्षा के लिए एक्सट्राने और प्रभावी प्रावधान लागू करें। किसानों के संगठनों, विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के साथतकाल और व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित करें, ताकि भारत की एक संतुलित और सुचित राष्ट्रीय स्थिति तैयार की जा सके। जैव विविधता और कॉर्पोरेट मुनाफे के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे बीजों पर हमारा नियंत्रण, हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। बीजों का उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। नई किस्में विकसित करने और उन पर आईपीआर लेने की अनुमति देना, जिससे डिजिटल बायोपायरेसी का एक नया और अप्रतिबंधित रास्ता खुल जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों और किसानों को बाद में इस जानकारी तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है। उनके डिजिटल जेनेटिक डेटा तक पहुंच सकती है। यह उन्हें आसानी से नई किस्में विकसित करने और उन पर आईपीआर लेने की अनुमति देगा, जिससे डिजिटल बायोपायरेसी का एक नया और अप्रतिबंधित रास्ता खुल जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों और किसानों को बाद में इस जानकारी तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है।

भारत की चुप्पी और किसानों की अनदेखी यह और भी चिंताजनक है कि भारत, जो इस कार्यकारी समूह का सह-अध्यक्ष है, ने अभी तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के किसानों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैसे संबंधित विभागों के साथ कोई राष्ट्रव्यापी परामर्श नहीं किया है। भारत के डॉ. सुनील अर्चक की सह-अध्यक्षता ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ा रही है, जिन पर देश के अंदर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है। भारत को अपनी समृद्ध जैव विविधता और अपने किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी। पूरी दुनिया के बीज क्षेत्र का केवल 1% एफएओ के लाभ-साझाकरण कोष में दान करने के बदले में हमारी पूरी आनुवंशिक संपदा को एमएलएस के लिए खोल देना भारत और वैश्विक दक्षिण की खाद्य संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है।

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited
(A Government of Chhattisgarh Undertaking)
(ISO 9001 : 2015 Certified)
1st Floor, Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibandha, Raipur (C.G.) - 492006
CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn No. 22AABCM6288NSZY
Phone : 0771-6621000 Fax : 0771-2583794
Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

NOTICE INVITING TENDER (1st call)
(e-Procurement Portal)

No.-: 08/CSIDC/E.E./Division-IV/2024-25/System No.171723 Raipur, Dated 08/07/2025

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur (CSIDC), a Government of Chhattisgarh Undertaking constituted under the Companies Act, engaged in Industrial Infrastructure Development & Other Related Activities in the State invites online tender in "Form-B" (Item Rate Basis) for the following works:-

S.No.	N.L.T. No.	Name of Work	Registered Contractor in CGPWD or in appropriate class in other dep't	Time allowed including rainy season	P.A.C. (INR Lacs)	EMD (INR Rs.)	Cost of Tender Doc. (INR) including GST 18%
1	08	B.T. Renewal Work and Construction of Hume Pipe Culvert at Industrial Estate Dhamdha Road Durg (C.G.)	D & Above	04 Months	81.12 Lacs	61,000/-	3540/-

The tender document containing detailed terms & conditions, scope of work and other details can be downloaded from the web portal (website) <https://eproce.cgstate.gov.in> from 08/07/2025 and Time 17:01 and shall be submitted online only. Amendment in tender, if any, will only be uploaded on the website and shall not be published in any newspaper.

NOTE: The interested tenderers for online submission of tender may contact CG eProc Helpdesk. Operated by Mjunction Services Limited., they may reach Helpdesk using 18002582502 (from 9 AM to 11 PM) (therein press 2 for CG e-Proc) or you can email them at Helpdesk_eproc@cgswan.gov.in

44472/4

Executive Engineer, Division-II
कार्यालय एवं दुकान हेतु स्थान उपलब्ध, वेबसाइट देखें www.csidc.in